भारत ने किया स्वदेशी तकनीक से बनी शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण

जागरण संवाददाता, बालेश्वर

- सतह से हवा में प्रहार कर दुश्मन को पल भर में नष्ट कर सकती है यह मिसाइल
- रक्षा मंत्री ने सफल परीक्षण के लिए विज्ञानियों और नौसेना को दी बधाई

भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर समुद्र तट से जमीन से हवा में तेज गति से प्रहार करने वाली कम दूरी की अत्याधुनिक शक्तिशाली मिसाइल वीएल-एसआरएसएएम का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी तकनीक से बनी यह मिसाइल शक्तिशाली है और पलभर में ही दुश्मन को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है तथा यह 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को तहस-नहस करने में सक्षम है। इसे नौसेना के लड़ाकू जहाज में लगाया जाता है। साथ ही यह जमीन से भी लांच किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान यह मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी और काफी तेज गति से हवा में सीधी ऊंचाई की ओर जाकर लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। इस परीक्षण के मद्देनजर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र के आसपास के ढाई किलोमीटर की परिधि में आने वाले छह गांवों के 3100 लोगों को एक दिन के लिए अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित किया गया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की टीमों की सराहना करते हुए मिसाइल निर्माण और परीक्षण टीम में शामिल विज्ञानियों तथा रक्षा अधिकारियों को बधाई दी है। कहा कि यह परीक्षण वीएल-एसआरएसएएम हथियार प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता की पुष्टि करता है।

वहीं डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के अध्यक्ष तथा विभाग के सचिव डा. समीर वी कामत ने भी इसमें शामिल टीमों को बधाई दी और कहा कि यह प्रणाली भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी।

चांदीपुर में गुरुवार को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा किया गया मिसाइल परीक्षण। प्रेट्र

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

साइबर कमांडो

डिजिटल धोखाधड़ी से मुक्ति की उम्मीद

स्मार्टफोन ने जहां एक ओर हमारे रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाया है, वहीं पिछले कुछ समय से इसके माध्यम से ठगी होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। साइबर फ्रॉड के मामलों में लगभग एक साल से 'डिजिटल अरेस्ट' के एक नए तरीके ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आम लोगों को इन मुश्किलों से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इसी सप्ताह 'साइबर कमांडो' के गठन की घोषणा की है। यह कदम साइबर फ्रॉड से निपटने में सक्षम साबित होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रयास के बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं

नई तकनीकों के प्रयोग से पिछले दो दशक से डिजिटल लेनदेन का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्मार्टफोन के आने के बाद से एक दशक से तो इसका उपयोग सामान्य हो गया है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट यह हुआ है कि वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी सामान्य हो गया है। साइबर धोखाधड़ी के कारण बीते महज एक साल के दौरान देश के लोगों ने 7,489 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठाया। इस साल शुरुआती चार महीने में ही लगभग आठ लाख साइबर फ्रॉड के मामले हुए, जिसमें लोगों के 1750 करोड़ रुपये ठग लिए गए। साइबर ठगी का एक नया तरीका सालभर पहले सामने आया और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वह काबू में नहीं आ रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। यह खतरनाक और चिंताजनक साइबर खतरा है- डिजिटल अरेस्ट।

डिजिटल अरेस्ट का मतलब है बिल्कुल वास्तविक लगने वाले ईडी, सीबीआइ, पुलिस अधिकारी बनकर अथवा उनके असली दिखते, परंतु बनावटी थाने, कार्यालय से फोन करके किसी को झूठ बोलकर भयग्रस्त कर देना। इस तरह के साइबर अपराधी लोगों को फोन करके उनके किसी करीबी के दुर्घटनाग्रस्त होने, तस्करी या ड्रग के मामले में फंसने या फिर गिरफ्तार होने की बात कहकर डरा देते हैं और पुलिस, ईडी आदि की गिरफ्तारी का भय दिखाकर घर से निकलने नहीं देते और भयादोहन कर धन वसूलते हैं। लोग घर में कैदी बन जाते हैं और फिरौती के रूप में भारी रकम चुकाते हैं और बाद में पता चलता है कि वे ठगी के शिकार हुए।

डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला पिछले साल दिसंबर में दर्ज किया गया था, जहां उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को मनगढ़ंत मनी-लांड्रिंग मामले में फंसाया गया। इसके बाद तो इस तरह की साइबर ठगी में व्यापक तेजी आ गई। इसमें जो शिकार बनते जा रहे हैं उनमें डाक्टर, साफ्टवेयर इंजीनियर, सेना के बड़े अधिकारी, आइआइटी प्रोफेसर जैसे ढेरों उच्च शिक्षित एवं जागरूक लोग शामिल हैं। साइबर अपराधियों ने लखनऊ की एक न्यूरोलाजिस्ट को सात दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर उसके सात खातों से लगभग तीन करोड़ रुपये का लेन देन किया तो एक अवकाश प्राप्त मेजर जनरल पांच दिन 'डिजिटल अरेस्ट' बने रहे, दो करोड़ की फिरौती के बाद उन्हें पता चला कि ठगे गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों में ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं।

संगठित आर्थिक अपराध : गृह मंत्रालय के अनुसार यह एक संगठित आनलाइन आर्थिक अपराध है और संभवतः इसे सीमा पार दुबई, पाकिस्तान में बैठे अपराधियों द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि अपने देश में भी इसके अपराधी पकड़े गए हैं। डेटा और सिस्टम में अनधिकृत घुसपैठ, डेटा चोरी, उसमें मनोवांछित या शरारतपूर्ण बदलाव, घोटाले या व्यवधान, इसके जरिए स्पैम वगैरह के काफी मामले पहले से ही आ रहे थे, इधर कुछ महीनों से एनसीबी, सीबीआइ, आरबीआइ और कानून प्रवर्तन अधिकारी के साथ साथ प्रदेश पुलिस के जवान बनकर लोगों को धमकाने और डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगने के भी बहुतेरे मामले सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने साइबर अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग को लेकर चेतावनी जारी की। यह एक लचर कदम था जो समस्या की गंभीरता के अनुकूल नहीं था।

गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई के बावजूद ब्लैकमेल और डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी बढ़ने लगे तो उसने हजार से ज्यादा स्काइप आइडी को ब्लाक किया जिसके जरिये अपराधी सरकारी अफसर बनकर ठगी करते थे। साथ ही सरकार ने टेलिकाम कंपनियों को निर्देश देकर 28 से अधिक सिम को ब्लाक और लगभग दो लाख सिम कार्डस को बंद या रि-वेरीफाई करने की कार्रवाई की। लेकिन बेहतर होने के बावजूद ये कदम नाकाफी साबित हुए। अब गृह मंत्रालय बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और आनलाइन फ्रॉड के मामलों की पहचान, जांच और उनसे निपटने के लिए दूसरे मंत्रालयों, उनसे संबद्ध एजेंसियों, आरबीआइ और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है जो फिलहाल सही दिशा लग रही है।

मंत्रालय इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को तकनीकी सहायता दे रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना इसीलिए हुई थी कि वह प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आइटी मध्यस्थों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाए, साथ ही साइबर अपराध से निपटने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार लाए। ये हितधारक मिलकर काम करेंगे तो फर्क साफ दिखेगा। 'साइबर कमांडो' कार्यक्रम देश में साइबर सुरक्षा की दिशा में एक समझदारी भरा कदम है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों से चुनिंदा जवानों को लेकर उन्हें आइआइटी कानपुर, मद्रास, कोट्टायम और रायपुर जैसे संस्थान द्वारा कठोर प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद इनकी विशेष शाखा स्थापित कर साइबर अरेस्ट जैसे अपराधों के खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित 'साइबर कमांडो' का उपयोग करना अच्छी योजना है। डिजिटल फोरेंसिक से लेकर साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में सब कुछ जानने वाले ये साइबर कमांडो जो आधुनिक साइबर हमलों की जटिलताओं से निपटने और भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होंगे, वे डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करने में राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की बेहतर सहायता करेंगे।

इस पहल से समन्वय प्लेटफार्म का साझा मंच डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध से संबंधित सभी सूचनाओं का व्यापक आंकड़ा केंद्र बन जाएगा, जिससे संबंधित राज्य सरकारों को इन जानकारियों को साझा करना सुगम हो जाएगा। इससे अपराधों के मानचित्रण और विश्लेषण के लिए एक मजबूत मंच बनेगा जो इसकी जांच के तरीके में क्रांति ला सकता है। जैसे-जैसे हमारा देश डिजिटल क्रांति को अपनाता जाएगा, वैसे-वैसे अपने साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत बनाने के जरूरत भी बढ़ती जाएगी। चूंकि साइबर अपराधों की संख्या, विस्तार और उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार द्वारा साइबर संसार में देश और देशवासियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐसे दूरदर्शी और सुविचारित कदम उठाने और अपने डिजिटल शस्त्रागार को नए हथियारों से लैस करना बहुत आवश्यक है, ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र साइबर अपराधियों से सुरक्षित हैं, यह सुनिश्चित हो। (ईआरसी)

नई पीढ़ी अधिक हो रही डिजिटल ठगी का शिकार

राजेंद्र शर्मा

सामान्य लोगों की तुलना में नई पीढ़ी ठगी का शिकार अधिक हो रही है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, आम आदमी की तुलना में जेन जी के युवा तीन गुना अधिक फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट मीडिया पर सर्वाधिक समय जेन जी की पीढ़ी ही दे रही है। वस्तुतः 1996 से 2010 के बीच जन्म लेने वाले युवाओं को जेन जी के नाम से पुकारा जाने लगा है। रोजमर्रा के जीवन में इंटरनेट पर निर्भरता इस पीढ़ी के लोगों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। रही सही कसर कोरोना के कारण आनलाइन पढ़ाई और 'वर्क फ्राम होम' ने पूरा कर दिया। इससे लोगों को स्मार्टफोन की लत इस तरह से लग गई कि लोग 'बिंज वाचिंग' का शिकार होते जा रहे हैं। वस्तुतः 'बिंज वाचिंग' पहली बार 2003 में चलन में आया, परंतु यह 2013 में अधिक लोकप्रिय हुआ। कोरोना काल में लाकडाउन के कालखंड में 'बिंज वाचिंग' और भी अधिक पांव पसारने में सफल रही। यह एक नए तरह का नशा हो गया है और इसमें लोग इंटरनेट मीडिया से जुड़े किसी भी प्लेटफार्म पर आने वाले लुभावने विज्ञापनों सहित विभिन्न प्रकार के आफर्स के चक्कर में आ जाते हैं।

स्मार्टफोन से खरीदारी का आदेश देना नए जमाने का नए तरह का नशा है। ड्रग्स की भाषा में बात करें तो यह डिजिटल ड्रग्स है और किसी अन्य नशे से इसका नशा किसी भी तरह से कमतर नहीं है। मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो यह एक तरह की वो बीमारी है जिसे मनोचिकित्सक साइकोसोमैटिक डिसआर्डर कहने लगे हैं।

'डेलाइट' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जेन जी के युवा अन्य की तुलना में तीन गुणा ज्यादा जालसाजों के शिकार इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी भोले भाव पर बहुत कम विश्वास करती है। यह पीढ़ी आसानी से आनलाइन आफर/ प्रपोजल्स आदि के जाल में फंस जाती है और किसी भी खरीद या निवेश पर पर्याप्त अध्ययन किए बिना या जानकारी जुटाए बिना, उसमें रकम लगा देती है। वैसे इसका एक कारण उनके पास समयाभाव को भी समझा जा रहा है। यहां कारण है कि डिजिटल दुनिया के जालसाज इंटरनेट मीडिया पर बड़े ही आकर्षक तरीके से अपने प्रस्ताव या अपने उत्पाद को प्रदर्शित करते हैं जिससे व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है। यहां तक कि साइबर ठगी का शिकार होने के साथ ही कई बार तो वह व्यक्ति अपनी जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठता है। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर आने वाले प्रस्तावों पर गंभीरता से सोच विचार कर ही निर्णय करना चाहिए। वह सही है कि इंटरनेट मीडिया के बहुत सारे लाभ सामने आए हैं, परंतु इसके साइड इफेक्ट्स को भी समझना होगा। सभी प्रकार के आनलाइन आफर सही नहीं होते, ऐसे में सही आफर और गलत आफर के अंतर को समझने की दृष्टि विकसित करनी होगी, फैक्ट चेक करना होगा, तभी जाकर स्वयं को ठगे जाने से बचाया जा सकता है। **(लेखक सामाजिक मामलों के जानकार हैं)**

रूस ने अपनी सेना से मुक्त किए 45 भारतीय

धोखे से भर्ती किए गए इन लोगों से रूसी सेना में लिया जा रहा था काम

पीएम मोदी ने गत जुलाई में रूस दौरे पर उठाया था यह मुद्दा

नई दिल्ली, रायटर: रूस की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीयों को मुक्त कराने की मोदी सरकार की कोशिशों को बड़ी सफलता मिली है। सरकार की इन कोशिशों का ही नतीजा है कि रूस ने अपनी सेना से अब तक 45 भारतीय नागरिकों को मुक्त कर दिया है। 50 और भारतीयों को मुक्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत जुलाई में रूस यात्रा के दौरान रूसी सेना में शामिल भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। रूसी सेना के साथ काम करते नौ भारतीयों की मौत हुई है।

मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, 'गत जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे और राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष यह मामला उठाया था। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 35 भारतीयों को मुक्त किया गया। जबकि उनके दौरे से पहले ही दस को मुक्त कर दिया गया था। अब तक 45 भारतीयों को मुक्त किया जा चुका है।' उन्होंने बताया कि इनमें से कई स्वदेश लौट चुके हैं और अन्य जल्द ही लौट आएंगे। रूसी सेना में अभी भी करीब 50 भारतीय हैं। इनको भी मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

रणधीर जायसवाल। फाइल

ज्ञात हो, जुलाई में मोदी मास्को गए थे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से कहा था कि उनकी सेना में जिन भारतीयों को रखा गया है, उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत के बाद रूसी सेना में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका व अन्य देशों के लोगों को शामिल किया गया। रूसी सेना में भर्ती भारतीयों ने गलत सूचना के आधार पर वहां भर्ती होने की बात कही थी। इसी तरह के आरोप नेपाली नागरिकों ने भी लगाए थे।

इजरायली कंपनियां भारतीयों के कामकाज से संतुष्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: इजरायल की ज्यादातर कंपनियां भारतीय कामगारों के कामकाज से संतुष्ट हैं। रणधीर जायसवाल ने एक प्रश्न के जवाब में कहा, यह सूचना इजरायल ने मुहैया कराई है। मंगलवार को आई इस रिपोर्ट में द्विपक्षीय नौकरी योजना के तहत गलत चयन का दावा किया गया था। भारतीयों को निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए इजरायल ले जाया जाएगा। यहां सात अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक लाख से ज्यादा फलस्तीनी श्रमिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौते के तहत हाल के महीनों में 4800 भारतीय इजरायल गए।

डोभाल की शोइगू से यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर चर्चा

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शांति प्रयास को सफल बनाने पर वार्ता
- भारत और रूस सहयोग की प्रगति पर भी हुई चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने गुरुवार को रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू से दोनों पक्षों के हितों वाले विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के संभावित तरीकों पर भी चर्चा की गई। पीएम नरेन्द्र मोदी ने जुलाई में यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का आह्वान किया था। उन्होंने जुलाई में रूस की यात्रा करने के बाद अगस्त में इस सिलसिले में यूक्रेन की यात्रा भी की थी।

डोभाल और शोइगू की यह बैठक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में चल रहे ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों के एनएसए के सम्मेलन से इतर हुई है। मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत-रूस ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति के साथ ही आपसी हित के कई अन्य अहम बिंदुओं पर भी विचार-विमर्श किया। डोभाल का यह दौरा मोदी के यूक्रेन दौरे के दो हफ्ते बाद हो रहा है। मोदी के यूक्रेन दौरे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से उनकी वार्ता में भी डोभाल उनके साथ थे। मोदी ने जेलेंस्की से कहा था कि दोनों देश युद्ध समाप्ति के लिए शांति वार्ता शुरू करें, भारत इसमें सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। मोदी ने कहा था कि भारत शांति के साथ है और वह बातचीत के जरिये समस्याओं का समाधान चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते व्लादिवोस्टक में ईस्टर्न इकोनोमिक फोरम की बैठक में यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए भारत, ब्राजील व चीन की मध्यस्थता स्वीकारने की बात कही थी। हाल ही में जेलेंस्की से वार्ता के बाद इटली की पीएम जार्जिया मेलोनी ने भी यूक्रेन में शांति बहाली में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया था।

सेंट पीटर्सबर्ग में गुरुवार को भारतीय सुरक्षा सलाहाकार अजीत डोभाल से मुलाकात करते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एएफपी

पुतिन ने फिर की मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति की प्रशंसा की है। कहा, दोनों देशों का विशेष रणनीतिक सहयोग जिस प्रकार से गतिशील है उसे देखकर प्रसन्नता होती है। भारत की प्रगति और उसे मजबूत होता देखकर एक दोस्त के रूप में हमें प्रसन्नता होती है। पुतिन ने यह बात बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग में एनएसए अजीत डोभाल से कही। पुतिन ने अक्टूबर में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की इच्छा जताई। उन्होंने मोदी की मास्को यात्रा को बेहद सफल बताया और अक्टूबर में काजान शहर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी के शामिल होने का इंतजार करने की बात कही।

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू

जहां कम वोट पड़े, वहां आयोग का विशेष सर्वे

भास्कर न्यूज | पटना

बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है। लेकिन निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मतदाता पुनरीक्षण का कार्य महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या इसी सूची के आधार पर तय होगी। बड़ी संभावना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ बदले जाएंगे। नए भी बनेंगे। आयोग, एक जनवरी 2025 को कट ऑफ डेट मानकर मतदाता सूची तैयार कर रहा है। यानी एक जनवरी को जो 18 साल के हो जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को बीएलओ के साथ नियमित बैठक कर लगातार समीक्षा का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक और सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों का अध्ययन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) कर रहे हैं। इनका काम उन कारणों का पता लगाना है, जिससे कम वोटिंग हुई।

लोकसभा चुनाव में वोटिंग की स्थिति

टॉप-10 क्षेत्र: 2019 की तुलना 2024 में अधिक वोटिंग हुई

काराकाट, जहानाबाद, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, सासाराम, बक्सर, नालंदा, पटना साहिब, वैशाली और मुंगेर।

टॉप-10 क्षेत्र: 2019 की तुलना 2024 में कम वोटिंग हुई

नवादा, बांका, जमुई, कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज, गोपालगंज, औरंगाबाद और गया।

*** जहां कम वोट वहां वोटिंग बढ़ाने पर विशेष फोकस होगा।**

सभी 243 सीटों पर समानांतर सर्वे भी चल रहा

सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे कम और सबसे अधिक मतदान वाले बूथों को चिन्हित कर सर्वे किया जा रहा है। ऐसे बूथों पर रिपोर्ट के आधार पर विशेष कार्रवाई होगी।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-सुधार का काम 2 चरणों में

पहला चरण : 20 अगस्त से शुरू हुआ है। 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सभी बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाता का सत्यापन, मतदान केंद्रों को चिह्नित करने, एपिक में गड़बड़ियों को दूर करने के साथ धुंधली तस्वीर में सुधार करना है। इसके तहत परिवार के सदस्यों का नाम एक ही प्रभाग में दर्ज करने, मतदाताओं की मतदान केंद्र से दूरी 2 किमी से कम रखने, मृत और दोहरीकरण प्रविष्टियों को हटाने, छूटे और भावी मतदाताओं का नाम जोड़ने सहित अन्य कार्रवाई होगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा 2 नवम्बर, 3 नवम्बर, 23 नवम्बर और 24 नवम्बर को विशेष अभियान की तारीख निर्धारित की गई है।

दूसरा चरण : प्रारूप प्रकाशन के बाद होगा। दावा-आपत्तियों का 24 दिसंबर तक निष्पादन किया जाएगा। 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

SC sets strict rules for preventive detentions

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: In a significant ruling that bolsters personal liberty, the Supreme Court on Thursday set stringent standards for authorities imposing preventive detention, making it mandatory to furnish all relevant documents and statements to the person being detained.

The decision, delivered by a bench headed by justice Bhushan R Gavai, emphasised the constitutional guarantee of personal freedom, and stressed the necessity for detainees to be provided with a fair and effective opportunity to challenge detention orders.

The bench, which also comprised justices Prashant Kumar Mishra and KV Viswanathan, ruled that the failure to supply all relevant documents and statements, especially in a language the detainee is conversant with, hampers their right to effectively contest the detention and, by extension, the constitutional right of effective representation.

Emphasising that the liberty of an individual is paramount and should be guarded zealously, the judgment set a high bar for detaining authorities, obliging them to not only inform detainees of the grounds of their detention but also ensure that all essential materials are provided in a comprehensible format. It further highlighted that authorities must guard against arbitrary actions and ensure that the rights of individuals under preventive detention are respected at every stage.

The decision emphasised the constitutional guarantee of personal freedom, and stressed the necessity for detainees to be provided with a fair opportunity to challenge detention orders. ANI

The 60-page judgment, authored by justice Gavai, held that the processes governing such detentions must adhere strictly to constitutional safeguards and that the prison authorities as well as the competent authority in the central government are obligated to decide a detainee's representation with "utmost expedition".

"In the matters pertaining to personal liberty of the citizens, the Authorities are enjoined with a constitutional obligation to decide the representation with utmost expedition. Each day's delay matters in such a case," asserted the bench.

The ruling came in response to a preventive detention order under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA), upheld by the Kerala high court. The Supreme Court overturned this decision, citing significant procedural lapses that violated the detainee's right of effective representation under Article 22(5) of the Constitution.

Drawing on the concept of personal liberty, the judgment cited Joy Adamson's classic Born Free to underscore the sanctity of individual freedom. It underlined that while preventive detention laws allow for curbing liberty, courts must ensure that such rights are not arbitrarily suspended. "The right to per-

continued on →9

15 SPs among 29 IPS officers shifted in Bihar

Avinash Kumar
avinash.kumar@htlive.com

PATNA: The Bihar government on Thursday transferred 29 IPS officers including SPs of 15 districts.

According to the transfers effected late on Thursday evening, the SPs of Bhojpur, Jamui, Aurangabad, Purnea, Samastipur, Nalanda, Nawada, Gopalganj, Rohtas, Buxar, Katihar, Lakhisarai, Sheohar, West Champaran and East Champaran districts have been replaced. Three City SPs of state capital and rural SP have also been transferred.

As per notification of home department, 2011 batch IPS officer Swapna G Meshram has been transferred and posted as commandant of Bihar special auxilary police (BSAP-3) and also given additional charge of BSAP-17. She replaced Deepak Ranjan, who was made AIG BSAP.

Nawada SP Ambrish Rahul replaces Meshram at Aurangabad. City SP (West) Patna, Abhinav Dheeman has been made new SP of Nawada.

West Champaran SP D Amarkesh has been made new SP of EoU and cyber training portal replacing Vaibhav Sharma, who has been shifted to Katihar. Katihar SP Jitendra Kumar has been transferred to SP (weaker section and women cell) replacing Navjot Simi. Jamui SP Shaurya Suman has been transferred to West Champaran in the place of D Amarkesh. City SP (Central, Patna) Chandra Prakash is replacing Suman at Jamui.

SPS OF BHOJPUR, JAMUI, PURNEA, SAMASTIPUR, NALANDA, BUXAR, ROHTAS, KATIHAR, ETC. HAVE BEEN TRANSFERRED

Lakhisarai SP Pankaj Kumar has been transferred and shifted to SCRB as SP. Ajay Kumar replaces him in Lakhisarai.

Darbhanga city SP Subham Arya has been made new SP of Buxar while Buxar SP Manish Kumar has been shifted to Central Selection Board of Constables (CSBC).

Purnea SP Upendra Nath Verma made commandant of BSAP-10. AIG (BSAP) Kartikey K Sharma replaces Verma at Purnea. Samastipur SP Binay Tiwari has been transferred to the post of superintendent of rail police, Muzaffarpur. Nalanda SP Ashok Mishra replaces Tiwari at Samastipur. Patna city SP (east) Bharat Soni has been made new SP of Nalanda.

Gopalganj SP Swarn Prabhat is shifted to East Champaran in same capacity in the place of Kantesh Mishra, who has been relieved for central deputation. Muzaffarpur city SP Awadhesh Dixit replaces Swarn Prabhat at Gopalganj. Bhojpur SP Pramod Kumar Yadav is transferred to special task force as SP (operation) while Bhagalpur city SP Mister Raj is made new SP of Bhojpur. Shoehar SP Anant Kumar Rai has been shifted to BSAP-16 as commandant. Outgoing commandant Shailesh Kumar Sinha replaced Anant, who will be the SP of Sheohar.

Waiting for posting Gaurav Mangla is shifted to rail as AIG and SP (special branch) Bam Bam Choudhary is now SP of Vigilance Investigation Bureau.

‘PM e-drive scheme to aid in faster adoption of EVs’

Press Trust of India
feedback@livemint.com

Auto majors M & M and Tata Motors hailed the PM e-drive scheme and said it would help in higher adoption of EVs. PTI

NEW DELHI: Home-grown auto majors Mahindra & Mahindra and Tata Motors on Thursday hailed the PM e-drive scheme, saying it would help in higher adoption of electric vehicles in the country.

On September 11, the Union Cabinet approved two major schemes with a total outlay of Rs 14,335 crore to promote the use of electric vehicles, including buses, ambulances and trucks.

The two schemes are the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme with an outlay of ₹10,900 crore over a period of two years, and the PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme with a budget of ₹3,435 crore. “With continued focused support on 2Ws, 3Ws, e-buses and the thoughtful addition of e-ambulances, the scheme will drive higher EV penetration in the country,” Mahindra & Mahindra managing director Anish Shah said in a statement.

Investments laid out for fast charging infrastructure for all segments will help in increasing consumer confidence for faster adoption of EVs, he added.

FAME and EMPS have helped in 20 per cent of electric three-wheeler penetration in the country, Shah said.

“With PM e-drive, we foresee India becoming the first country to achieve 100% electrification in this segment by 2030,” he added.

Tata Motors Executive Director Girish Wagh said the scheme will accelerate India’s journey towards zero-emission mobility with greater speed and rigour, especially in trucks, buses and the ambulance segment. “We continue to collaborate with the Government and other stakeholders in this nation-building endeavour towards sustainable transportation,” he added.

Ola founder Bhavish Aggarwal said the scheme is a strong push to boost EV adoption.

“The PM E-Drive scheme is a welcome move and a great step to accelerate EV adoption in India. The scheme will provide the required impetus to the EV industry to scale and mature rapidly, ensuring a swift transition from ICE to EVs,” he tweeted.

Wardwizard Innovations & Mobility chairman and MD Yatin Gupte said the progressive step will drive India towards self-reliance and a greener future.

Switch Mobility CEO Mahesh Babu said the scheme would benefit 24 lakh vehicles, including 28,000 electric buses.

“With about 2,000 orders in hand for SWITCH, we foresee a 45-70% CAGR growth over the next 10 years, depending on government schemes like the PM E-Drive,” he added.

Under the scheme, subsidies/demand incentives worth ₹3,679 crore have been provided for e-2Ws (electric two-wheelers), e-3Ws (electric three-wheelers), e-ambulances, e-trucks and other emerging EVs.

The scheme will support 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-buses.

Earlier, the government had implemented the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle (FAME) scheme in two phases. About 16 lakh electric vehicles were supported under FAME 1 and FAME 2 schemes.

Health care using AI is bold, but much caution first

News about the possibility of a "free AI powered primary-care physician for every Indian, available 24/7" within the next five years is ambitious. It raises critical questions about feasibility, sustainability, and the readiness of India to tackle such enormous undertakings.

Primary health care (PHC) ensures the right to the highest attainable level of health by bringing integrated services closer to communities. It addresses health needs, tackles broader health determinants through multisectoral action, and empowers individuals to manage their health. We risk undermining this fundamental aspect of PHC by relying on Artificial Intelligence (AI) as it is impersonal, making people passive recipients of care rather than active participants.

AI excels in processing and automating repetitive tasks but lacks characteristics of human intelligence such as understanding the physical world, retrieving complex information, maintaining persistent memory, and engaging in reasoning and planning. These are all fundamental to medicine, where understanding the nuances of a patient's condition goes beyond pattern recognition.

Delivering health care demands a human-centric approach of empathy and cultural understanding. Consciousness – the awareness and understanding of the real-world environment – underpins human decision-making, distinguishing human intelligence from AI. AI cannot replicate the moral and ethical reasoning that comes from conscious experience. Unlike other domains, health-care data is scattered, incomplete and often inaccessible for AI training, making it difficult to train a model.

Data, models and issues

Naegele's rule from obstetrics, which has been in use for over 200 years, can be used to highlight the challenges in health care. It is based on 18th century reproductive habits of European women, which may not be applicable today. This method is used to predict the birth date of a child during pregnancy. It relies solely on the length of the last menstrual cycle and has a 4% accuracy. It fails to account for critical factors such as maternal age, parity, nutrition, height, race, and uterus type, which are essential for accurate prediction. Developing a better predictive model than Naegele's rule requires vast amounts of personal data, which belong rightfully to patients. This illustrates the inherent paradox in AI development in health care – the need for extensive data collection to improve accuracy is at odds with privacy and ethical concerns.

Dr. C. Aravinda

an academic and public health physician

India cannot jump into AI-driven health care without first addressing the foundational issues within its health system

The costs involved in establishing infrastructure to capture, collect, and train this data are substantial. As reproductive health and fertility rates change over time, constant fine-tuning of AI models is necessary, leading to recurring expenses. Health-care data is complex and personal, making it difficult to standardise it across populations.

India's diversity complicates the issue further. This diversity means that data for AI models must be extensive and deeply contextualised, but generating such data requires access to personal and behavioural information.

AI's utility in health care

AI can play a crucial role in specific, well-defined tasks within health care, particularly through narrow intelligence, diffusion models and transformers. Narrow intelligence focuses on specialised tasks such as predicting hospital kitchen supply needs, managing biomedical waste, or optimising drug procurement. Diffusion models, which are adept at predicting patterns from complex datasets, can help screen histopathology slides or screen only a subset of the population using medical images.

Large Language Models (LLMs) and Large Multimodal Models (LMMs) are emerging as powerful tools in medical education and research writing. These can provide rapid access to medical knowledge, simulate patient interactions, and support the training of health-care professionals. By offering personalised learning experiences and simulating complex clinical scenarios, LLMs and LMMs can complement traditional medical education

A significant issue with AI in health care is the "black box" problem, where the decision-making processes of AI algorithms are not transparent or easily understood. This poses risks in health care, where understanding the rationale behind a diagnosis or treatment plan is critical. Health-care providers are left in the dark about how certain conclusions are reached, leading to a lack of trust and potential harm if the AI makes an incorrect or inappropriate recommendation.

Google DeepMind's AI mysterious algorithm defeating world-class players in the GO game (board game) can be celebrated. While such feats are acceptable for games, they raise concerns in real-life health-care decisions. The stakes are serious in human health, where the consequences of a mistake can be life-threatening.

India and the issue of AI governance

A recent petition in the Kenyan Parliament by content moderators against OpenAI's ChatGPT has highlighted the ethical complexities in AI development, revealing the exploitation of underpaid workers in training AI models. This raises concerns about the exploitation of vulnerable populations in AI training. It underscores the importance of safeguarding the interests of Indian patients because the data required to train the model legally belong to patients.

While population-level data generated by health systems can be useful, it is prone to ecological fallacy. India lacks comprehensive regulation or legislation addressing AI such as the European Union Artificial Intelligence Act, making it all the more critical. AI tools in health care must be developed and deployed with the core medical ethics of "Do No Harm".

AI-powered health care in India promises increased efficiency and reduced error rates. Advanced AI technologies require significant investments in research, data infrastructure, and continuous updates – costs that someone must bear. India cannot leapfrog into AI-driven health care without first addressing the foundational issues in its health system. The complexities of patient care, the need for high-quality data, and the ethical implications of AI demand a more measured approach.

The views expressed are personal

A 16-point document on judicial values was adopted by SC in 1997

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The observations in public fora and within the legal fraternity about the propriety of Prime Minister Narendra Modi's videographed visit to the residence of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud to participate in Ganesh puja are grounded in a 16-point document on judicial values adopted in a Full Court Meeting of the Supreme Court on May 7, 1997.

The document called the "Restatement of Values of Judicial Life" is an illustrative, and not exhaustive, guide of what is expected of Supreme Court and High Court judges.

"The behaviour and conduct of members of the higher judiciary must reaffirm the people's faith in the impartiality of the judiciary. Accordingly, any act of a judge of the Supreme Court or a High Court, whether in official or personal capacity, which erodes the credibility of this perception has to be avoided," the very first tenet of the document reads.

It recommends a judge to practice "a degree of aloofness consistent with the dignity of his office".

"Every judge must at all times be conscious that he is under the public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held," the document cautions.

The Campaign for Judicial Accountability and Reforms, of which advocate Prashant Bhushan is an office-bearer, said the established practices of judicial conduct place an emphasis on maintaining public confidence through probity in the interaction between high constitutional functionaries.

"As then CJI M.N. Venkatachaliah put it to former Prime Minister Narasimha Rao, the relationship between the judiciary and executive has to be correct, not cordial, and cordiality between court and government has no place in our constitutional scheme of checks and balances. The judiciary... must be seen as entirely independent from the Executive branch," the statement said.

Senior advocate Kapil Sibal said the Chief Justice of India was a man of great integrity. "The issue is not the individual; the issue is what such a video clip has on the minds of the people... If there is gossip around it, it is not fair on the institution. You should not lend yourself to a situation, to be in a situation where people can gossip about the institution and start speculating. My religion and my way of expressing in the context of my beliefs is a private matter," he said.

Lively interaction: Prime Minister Modi shares a light moment with the para-athletes. (Right): The medal-winners proudly show their medals at the felicitation function hosted by Indian Oil along with PCI. ANI & PTI

Paralympians meet PM, Indian Oil announces scholarships at felicitation

Javelin thrower Sumit dedicates his gold to Modi; IOC to introduce medical insurance and sports kits for para-athletes as part of its commitment

PARALYMPICS

Sports Bureau
NEW DELHI

Having bettered its own previous best medal haul at the Paris Paralympics, the PCI is confident of inching closer to 50 medals at the 2028 LA Games. Paralympic Committee of India president Devendra Jhajharia insisted on Thursday that the country's para sportspersons will better their tally and get at least 40-50 medals in the next edition. India went from 19 medals in Tokyo to 29 at Paris.

"I want to thank everyone for the support they have shown for our para-athletes. Felicitations and encouragement from government and corporates will only motivate them to do better. I am confident that in LA 2028 we will only get better from here.

PCI president's promise

"I promise everyone on behalf of the athletes that we will win at least 40 to 50 medals in the next edition," Jhajharia said during a function hosted by the Indian Oil Corporation along with PCI here.

IOC had signed an MoU with the PCI in October last year as part of its Road to Paralympics 2024 programme that included support for para-athletes at the Asian Para Games and the World Para Shooting Championships, besides Paris.

P&NG ministry secretary Pankaj Jain, emphasising the need to enhance existing support for para athletes from oil companies, announced that Indian Oil would be introducing monthly scholarships, medical insurance and sports kits for para-athletes as part of its commitment.

It was a busy day for the Paralympians who met Prime Minister Narendra Modi earlier in the day and interacted with him, thanking him for constant encouragement and support.

"The way you have accepted and supported para-athletes is unprecedented," high jumper Sharad Kumar said.

Javelin thrower Sumit Antil dedicated his gold to the PM, saying it was his way to keep the promise made after Tokyo Paralympics to bring back another gold even as the PM teased Navdeep Singh for his aggressive celebrations.